बेरोज़गारी: कारण और उपाय



"अब कोई युवा नहीं रहेगा बेकार, अब की बार मोदी सरकार" ऐसा आश्वासन देते हुए मोदी 2014 में सत्ता में आए. अब मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं, लेकिन परिस्थित में कोई सुधार होने के बजाय उल्टा बेरोज़गारी की परिस्थिती पिछले 45 सालों में सबसे बदतर हो गई है. कहीं लॉकडाऊन में नौकरी छूट जाने की वजह से, तो कही किसी विद्यार्थी ने नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्या की खबरें हर रोज़ सुनने को मिल रही हैं. उसी तरह, इस बेरोज़गारी की समस्या के कारण अपराध, हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार आदि सामाजिक समस्याए भी बढ़ी है.

कैसी है बेरोज़गारी की स्थिति?

मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में रोज़गार निर्मिती बहुत ही कम हुई है. वर्ष 2016 में तो 8 श्रमप्रधान उद्योगों (सबसे अधिक कामगारों की ज़रूरत वाले क्षेत्र) में मात्र 2.31 लाख नौकरियाँ ही निर्माण हुई हैं. **सिर्फ लॉकडाऊन की वजह से देश में** 2.1 करोड़ पगारदार नौकरियाँ खत्म हुई. इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करनेवाले करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए.

वर्ष	कुल रोज़गार
2011-12	47.42 करोड़
2017-18	46.50 करोड़

बेरोज़गारी के कारण क्या हैं?

विद्यालयों, कॉलेजों, अख़बारों, टीवी और इस तरह के सभी माध्यमों द्वारा बेरोज़गारी का एक मात्र कारण बढ़ती जनसंख्या बताया जाता है; लेकिन वास्तव में क्या जनसंख्या बेरोज़गारी का कारण है, आइए देखते है-

बेरोज़गारी के सवाल पर सोचते हुए जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व पर ध्यान देना चाहिए.

देश	जनसंख्या घनत्व
ब्राज़ील	25
जापान	348
इज्राईल	394
भारत	460
नेदरलैंड्स	507
दक्षिण कोरिया	527
ताईवान	671

जनसंख्या के घनत्व का मतलब है कि, किसी देश में प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या. मानिए कि एक देश की जनसंख्या 100 है और क्षेत्रफल 5 वर्ग कि.मी. है, तो उस देश का जनसंख्या घनत्व होगा 100 बटे 5, यानी 20. उदाहरण के तौर पर ब्राज़ील आकार में भारत से बड़ा देश है; लेकिन जनसंख्या बहुत कम है. हमारी तुलना में तो बहुत ही कम. लेकिन फिर भी वह हमारे उतना ही विकासशील देश हैं. दूसरी तरफ़ नेदरलैंड्स (507), दक्षिण कोरिया (527), ताईवान (671) इनका जनसंख्या घनत्व भारत से बहुत ज्यादा है; लेकिन फिर भी हमसे अधिक विकसित हैं, और नौकरियों की संख्या भी ज्यादा है. यदि जनसंख्या कारण होता, तो फिर ब्राज़ील में कोई समस्या ही नहीं होती और ताईवान, नेदरलैंड्स हमसे ग़रीब होते. इसका निष्कर्ष यह है कि –

जनसंख्या और बेरोज़गारी का कोई संबंध नही होता!

असली कारण क्या हैं?

बेरोज़गारी के मूल कारणों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जनसंख्या जैसे कारणों को सामने रखा जाता है. वास्तव में बेरोज़गारी बढ़ने के लिए सरकार की जनविरोधी और पूँजीपतियों के हितों के अनुकूल नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं.

भारतीय कृषि क्षेत्र का विनाश: आज भी देश की 50% जनता अपने रोजगार के लिए कृषी क्षेत्र पर निर्भर है. इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर सरकार का खर्चा बहूत ही कम है. (2018-19 में भाजप सरकार का खेती के उपर का खर्चा: सिर्फ रु. 57 हजार करोड) इसके चलते किसान का लागत मुल्य बढ़ा पर आमदनी घट गयी और खेती घाटे का सौदा बन गया. किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो गया. सरकार की इन किसान विरोधी कृषी नितियों कि वजह से देश की खेती देशी-विदेशी कृषी कंपनियों के नियंत्रण मे जा रही है. परिणाम: बेरोजगारी! और अभी सरकार के तीन नए कृषी कानूनो के चलते यह परिस्थिती और भी बिकट होगी.

घटती सरकारी नौकरियाँ: शिक्षा, स्वास्थ, परिवहन, प्रशासन, संशोधन जैसे कई क्षेत्रों में सरकार 'कंगाली' का कारण देकर नई नौकरियाँ तयार

नहीं कर रही. सरकारी क्षेत्र में पुरे देशभर में लाखो पद रिक्त है. वो भरने के बजाय सरकार सरकारी नौकरियाँ घटा रही है. परिणाम: बेरोजगारी!

बढ़ता निजीकरण: विनिवेश (Disinvestment) के नाम पर सरकार रेल्वे, बँक, LIC, एअर इंडिया, BPCL जैसी 50 से अधिक सरकारी कंपनिया कौड़ीयों के दाम पर देशी-विदेशी कंपनियों को बेच रहीं है. निजी कंपनियों मुनाफा बढ़ाने के लिए ठेका (काँट्रक्ट) पद्धती पर कम से कम लोगों से अधिक से अधिक काम करवाया जाता है. परिणाम: बेरोजगारी!

नोटबंदी-जीएसटी-लॉकडाऊन: नोटबंदी के वजह से नगद रकम पर चलनेवाले लाखो छोटे व्यवसाय

बंद हो गये जिससे करोडो लोग बेरोजगार हो गये. जी.एस.टी जैसी नीतीयों की वजह से भी छोटे व्यवसायों पर बुरा प्रभाव पड़ा है. परिणामतः लाखो लोग बेरोजगार हुए. इन दोनों के एकत्रित परिणामस्वरुप देश का अनौपचारिक क्षेत्र पुरी तरह से तबाह हो गया.

जिस तरह से मोदी सरकार देश चला रही है, यह स्पष्ट है की बेरोजगारी की परिस्थिती और गंभीर होनेवाली है!

फिर नौकरियों का निर्माण कैसे होगा?

कृषि क्षेत्र पर सरकारी खर्चा बढ़ाकर – यदि सरकार तय कर ले, तो देश में करोड़ों नौकरियों का निर्माण कर सकती हैं. सबसे पहले तो, देश की 50% जनता जिस खेती पर निर्भर है, उसमें अगर सरकार निवेश बढ़ाए, बीज – खाद – बिजली पर सबसिडी और फसल को उचित न्युनतम दाम दे, तो खेती और खेती से जुड़े अन्य व्यवसायों द्वारा हमारे गाँवों में ही बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध होंगे.

सरकारी नौकरियाँ बढ़ाकर - पहले सरकारी नौकरियों की उपलब्धता वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक थी. 1991 में लागू किए गए निजीकरण—वैश्वीकरण—उदारीकरण की नीतियों के कारण सरकारी नौकरियों में भारी गिरावट आयी है. अमेरिका में हर 1 लाख जनसंख्या के पिछे 7,170 सरकारी नौकरियाँ हैं, वहीं भारत में सिर्फ 1,200! यदि अमेरिका की तरह भारत में भी सरकारी नौकरियों की निर्मिती हुई, तो भारत में लगभग 8 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा होंगी.

रोजगार गारंटी योजना लागू कर: मनरेगा योजना पर सरकारी खर्चा बढ़ाकर इसे गाँव के साथ-साथ शहरों में भी प्रभावी तरीके से लागू करने पर करोड़ो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देकर: इस क्षेत्र से लगभग 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है. अगर इस क्षेत्र को सरकार सबसिडी, कम ब्याज पर कर्जा और उत्पादों को बाज़ार मुहैय्या कराए तो इससे कई करोड़ रोज़गार पैदा होंगे.

संघटित क्षेत्र में अधिक रोजगार - निजी कंपनियाँ मजदूरों को दी जाने वाली तनख़्वाह से लगभग चार गुना अधिक मुनाफ़ा कमाती हैं. कंपनियों का मुनाफ़ा यदि नियंत्रित किया, तो मज़दूरों की संख्या और तनख्वाह दुगुनी हो सकती है.

इसके लिए पैसा कहा से आएगा?

सरकार कहती है कि नौकरियाँ निर्माण करने के लिए पैसा नहीं हैं. सच्चाई यह है कि पैसा है, लेकिन सिर्फ़ अमीरों के लिए! जनता के टॅक्स का पैसा सरकार रोजगार निर्मिती पर खर्च न करते हुए बड़े-बड़े अमिरों पर खर्च करती है. पिछले 6 सालों में उद्योगपितयों और अमीरों को 30 लाख करोड़ रुपए की टैक्समाफ़ी दी गई है और 22 लाख करोड़ रुपए की कर्ज़माफ़ी की है. कॉपोरेट टॅक्स 34% से घटाकर 24% कर दिया है. अमीरों के उपर का संपत्ती कर खत्म कर दिया है. सरकार के पास पैसा आ सकता है अगर वह —

देश के 1% **अमिरों पर 2% संपत्ति कर और 33% विरासत कर** लगाए. इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और वो पैसा जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेन्शन व कई और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए खर्च किया जा सकता है. इसीसे

ढेर सारे रोज़गार भी पैदा होंगे!

हमें क्या करना होगा?

दोस्तों, झूठे आश्वासन देकर सत्ता में आई इस मोदी सरकार ने आम जनता के साथ धोखा किया है. ऐसी परिस्थिति में हमें निराश न होते हुए इसे बदलने के लिए हम सभी को संगठित होकर विकल्प खड़े करने की ज़रूरत है. हम भी आपकी अपना काम या पढ़ाई करते है और अपने जीवन का कुछ समय सामाजिक कामों में देते हैं. हम आपका आवाहन करते हैं की आप भी हमारी कोशिशों में शामिल हों. हमारे बारे में अधिक जानने

के लिए और हमारे कार्यक्रमों में सहभागी होने के लिए नीचे दिए हुए पतों पर हमसे संपर्क करें.

मिट्टी सत्याग्रह

संपर्क पता: v-1, गणेश प्रसाद, नौशीर भरुचा मार्ग, ग्रांट रोड (पश्चिम), मुंबई -400007

🕓 गुड्डी – 7738082170

सुनीति सु. र. – 9423571784

फिरोज़ मीठीबोरवाला - 9029277751

